प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

14.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 09:20बजे

''आज के मुख्य समाचार''

- उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन आज केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। मेधावियों को वितरित करेंगे डिग्रियां।
- केन्द्र ने कहा–देश की रिफाइनरियों में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लागू होने से गांवों में सुनिश्चित हो रही स्वच्छता की राह।
- प्रदेश के सभी न्यायालयों में आज आयोजित की जाएंगी राष्ट्रीय लोक अदालतें।

दीक्षांत समारोह

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन आज केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति सतप्रकाश बंसल ने बताया कि राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सहित अन्य गणमान्य लोग भी समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान 12 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 5 सौ 24 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। श्री राधाकृष्णन धर्मशाला स्थित युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे।

संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि सभी रिफाईनरियां शत–प्रतिशत क्षमता से काम कर रही है और रिफाइनरियों में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा कि घरेलू पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति बिना किसी कटौती के हो रही है।

मुख्य सचिव

इधर प्रदेश मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में पैट्रोल डीजल व एल.पी.जी. की पर्याप्त मात्रा है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने शिमला में बताया कि प्रदेश में रसोई गैस और व्यवसायिक सिलेंडरों की भी कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार ने इसके लिए नागरिक आपूर्ति के तहत स्टॉक जारी किया है। मुख्य सचिव ने बताया कि एल.पी.जी. की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है।

एलपीजी–चंबा

चंबा के उपायुक्त उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा है कि चम्बा में घरेलू रसोई गैस, पेट्रोल व डीज़ल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और नियमानुसार इन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उपभोक्ताओं को की जा रही है। उन्होंने लोगों से इस सम्बन्ध में भ्रामक प्रचार से बचने की अपील की है।

हरियाणा–राज्यसभा

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। क्रॉस वोटिंग और जोड़–तोड़ की आशंका के बीच हरियाणा कांग्रेस ने अपने 31 विधायकों को शिमला भेज दिया है। ये सभी विधायक शिमला के समीप कुफरी के एक निजी होटल में ठहरे हुए हैं। प्रदेश सरकार ने विधायकों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं और होटल के बाहर पुलिस का पहरा लगाया गया है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और तब तक कांग्रेस विधायकों के शिमला में ही ठहरने की सूचना है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य लगभग पूरा होना शिक्षा जगत के लिए सकारात्मक संकेत है और इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। कल देर सांय धर्मशाला पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस को आरटीआई के दायरे से बाहर करने के फैसले का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रदेशहित में नहीं है और इससे एजेंसियों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ सकती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर दुनिया के कई देशों पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि भारत में गैस और तेल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी और इसके लिए केंद्र सरकार लगातार संबंधित देशों के संपर्क में है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में हिमाचल ने शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए सिक्किम के बाद देश के दूसरे खुले में शौच मुक्त राज्य के रूप में जगह बनाई है। मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 1 लाख 96 हज़ार से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 प्रतिशत आबादी के साथ राज्य ने ग्रामीण स्वच्छता में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और वर्ष 2016 में खुले में शौच मुक्त राज्य बना। राज्य के 78 प्रतिशत गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है जबकि 86 प्रतिशत गांवों में ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के ऊना जिले में भी मिशन के तहत बेहतरीन कार्य किया गया है।

गृह मंत्रालय–केंद्रीय सहायता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने पिछले वर्ष अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से प्रभावित हिमाचल प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों के लिए एक हजार नौ सौ बारह करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लिए 2 सौ 88 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। मंत्रालय ने बताया कि यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष–एसडीआरएफ में जारी की गई उस धनराशि के अतिरिक्त है जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है।

लोक अदालत

प्रदेश उच्च न्यायालय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्तवाधान में आज राज्य के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न अदालतों द्वारा अभी तक लगभग 82 हजार मामलों की पहचान की गई है। इस दौरान ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालयों में एम.वी. चालान मामलों में ई–कोर्ट डिजिटल के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की ऑनलाईन सुविधा प्रदान की गई है।

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर

आज समाचार पत्रों ने अलग–अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है–कांगड़ा के ज्वाली स्कूल में शिक्षकों ने खुद करवाई सामूहिक नकल; परीक्षा केंद्र रद्द चार निलंबित। इसी अखबार की एक अन्य खबर है– बिजली प्रोजेक्टों पर भू–राजस्व लगाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती–सरकार ने जबाव तलब।

दिव्य हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है– 14 माह में लोकतंत्र की मंडी में बिक गए पूर्व विधायक। पंजाब केसरी के शब्द हैं–हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थिति पंजाब से बेहतर। जबकि दैनिक जागरण की सुर्खी है–हिमाचल की आर्थिक स्थिति बेहतर, पंजाब अपनी चिंता करे।

हिमाचल दस्तक की खबर है–मई में बिना किसी विघ्न के एक साथ संपन्न करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव।

मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है– लाहौल में तीसरे दिन बर्फबारी से पर्यटक बढ़े, दो दिन में करीब 25 हजार सैलानी पहुंचे मनाली।

''अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर''

- उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन आज केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। मेधावियों को वितरित करेंगे डिग्रियां।

- केन्द्र ने कहा–देश की रिफाइनरियों में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार।

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लागू होने से गांवों में सुनिश्चित हो रही स्वच्छता की राह।
- प्रदेश के सभी न्यायालयों में आज आयोजित की जाएंगी राष्ट्रीय लोक अदालतें।